निवेश

यूपीसीडा की जमीनों पर बस रहीं औद्योगिक इकाइयां

आठ जिलों में 150 करोड़ की 100 इकाइयों का बनेगा रिकॉर्ड

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। इस वर्ष दिसंबर तक प्रदेश में 100 से 150 करोड़ की 100 नई इकाइयां कार्यशील हो जाएंगी। खास बात ये है कि ये इकाइयां नोएडा, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं लगेंगी बल्कि अमेठी, संडीलास त्रिशुंडी, पीलीभीत, बरेली, भरुआ सुमेरपुर और कोसी में लग रही हैं।

इन इकाइयों में न्यूनतम 12 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। यूपीसीडा ने सभी इकाइयों को जमीन सहित सभी एनओसी जारी कर दी हैं। किसी प्राधिकरण द्वारा महज छह महीने में 100 इकाइयों को धरातल पर उतारने की ये अनूठी उपलब्धि होगी।

निवेशक सम्मेलन के दौरान किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी यूं तो सभी विभागों को दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक

विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की है।

इनमें से यूपीसीडा ने इस वर्ष दिसंबर तक 100 नई इकाइयों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत इकाइयों को जमीन आवंटन किया जा चुका है। उनका निर्माण शुरू हो चुका है। एक तिहाई का अंतिम चरण में है। इनमें से आधी से ज्यादा इकाइयां अमेठी, संडीला, त्रिशुंडी, कोसी, पीलीभीत, बरेली, कानपुर देहात और भरुआ सुमेरपुर में स्थापित हो रही हैं। इनमें से कुछ मेगा श्रेणी की इकाइयां हैं।

पीलीभीत में ए बी मौरी (2000 करोड़), बरेली में डेयरी क्राफ्ट (300 करोड़), फर्रुखाबाद में सोम डिस्टेलरी (700 करोड़), बंदायू में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (500 करोड़). संडीला में ग्रीनप्लाई (350 करोड़), बारावंकी में गोदरेज एग्रोवेट (250 करोड़), जगदीशपुर में स्काईलार्क पोल्ट्री (200 करोड़) प्रमुख हैं। ये सभी इकाइयां यूपीसीडा द्वारा आवंटित भूखंडों पर आकार ले रही हैं।

इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और उन्नाव वेयरहाउसिंग का बड़ा गढ़ बनकर उभरे हैं। इस बेल्ट में 20 से ज्यादा बड़े वेयरहाउस बन रहे हैं या बनकर तैयार हैं। इनमें 5000 करोड़ का निवेश हुआ है। खास बात ये भी है कि पिछले एक वर्ष में 1400 से ज्यादा इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इन इकाइयों में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।